सोना चमका, चांदी टूटी फिर दौड़ी

24 कैरेट का सोना हुआ 1.37 लाख पार

हफ्तेभर में गोल्ड ने 3,100 से ज्यादा की छलांग लगाई

नई दिल्ली, 11 जनवरी. सोना और चांदी एक बार फिर निवेशकों और ज्वेलरी खरीददारों के लिए चर्चा का विषय बन गए हैं. बीते एक सप्ताह में दोनों की कीमतों में जिस तरह का उतार-चढ़ाव देखने को मिला, उसने बाजार को बेहद रोमांचक बना दिया.

जहां एक ओर चांदी ने तेज गिरावट के बाद अचानक छलांग लगाकर निवेशकों को चौंकाया, वहीं सोने ने भी मजबूत पकड़ बनाते हुए अपने ऊपरी स्तरों की ओर रुख किया. महंगाई, वैश्विक तनाव और डॉलर की चाल के बीच कीमती धातुओं को सुरक्षित निवेश माना जाता है. यही वजह है कि जब भी बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, सोना-चांदी की मांग बढ़ जाती है. जनवरी के पहले सप्ताह में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब चांदी अपने उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गई, जबकि सोने ने भी शानदार मजबूती दिखाई.

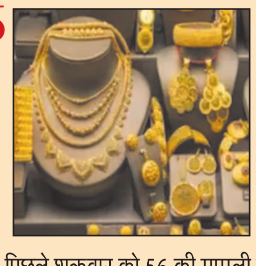

हाई लेवल की बात करें तो चांदी अब भी अपने रिकॉर्ड स्तर से नीचे है. अपने उच्चतम स्तर 2,59,692 की तुलना में यह अभी भी 7,690 प्रति किलो सस्ती मिल रही है, जिससे निवेशकों को एक बार फिर खरीदारी का अवसर नजर आ रहा है. सोने की बात करें तो एमसीएक्स पर 5 फरवरी एक्सपायरी वाला गोल्ड पिछले शुक्रवार को 56 की मामूली बढ़त के साथ 1,38,875 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. 2 जनवरी को यही भाव 1,35,761 था, यानी सिर्फ एक सप्ताह में सोना 3,114 महंगा हुआ. हालांकि सोना अभी भी अपने ऑल-टाइम हाई 1,40,465 से ?1,590 नीचे है. घरेलू बाजार में इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 1,37,120 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट 1,33,830 और 20 कैरेट 1,22,040 पर रहा.

अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करने या ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं, तो मौजूदा रेट और बाजार की चाल को समझना बेहद जरूरी है. खासकर यह जानना अहम है कि चांदी अपने हाई से कितनी सस्ती है और सोना कितने स्तर पर कारोबार कर रहा है. बीते सप्ताह सोना-चांदी के बाजार में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी ने पहले जोरदार तेजी दिखाई और फिर हल्की गिरावट के साथ सप्ताह का अंत किया. 2 जनवरी को 5 मार्च एक्सपायरी वाली चांदी का वायदा भाव 2,36,316 प्रति किलोग्राम था, जो अगले कुछ कारोबारी सत्रों में तेजी से बढ़ते हुए 2,59,692 के उच्च स्तर तक पहुंच गया.

उर्वरकों पर जीएसटी पांच प्रतिशत हो : आईएमएमए

नई दिल्ली, 11 जनवरी. इंडियन माइक्रो-फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएमएमए) ने केंद्र से आग्रह किया है कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत अधिसूचित सभी उर्वरकों पर वस्तु एवं सेवा कर की दर को समान रूप से घटाकर पांच प्रतिशत किया जाए. एसोसिएशन ने केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अपनी बजट पूर्व सिफारिशों में उर्वरक क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने और %ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बड़े नीतिगत सुधारों की मांग की है. एसोसिएशन ने बताया कि जीएसटी 2.0 की शुरुआत के बाद कुछ खास मदों पर टैक्स 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करना एक ऐतिहासिक सुधार था, लेकिन अब भी कुछ चीजों पर अधिक जीएसटी लग रहा है.

भारत-ईयू वार्ता में कार्बन कर चुनौती

अमेरिकी दबाव के बीच भारत-ईयू व्यापार वार्ता सक्रिय

कार्बन कर और कृषि सब्सिडी पर भारत-ईयू समझौते की कोशिश

नयी दिल्ली, 11 जनवरी. भारत पर शुल्क और बढ़ाने तथा ग्रीनलैंड अधिग्रहण जैसी अमेरिका की धमकियों के बीच भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने आपस में मुक्त व्यापार समझौते के लिए चल रही बातचीत में कार्बन कर और कृषि सब्सिडी जैसे कुछ मुद्दों पर मतभेद दूर करने और समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के प्रयास तेज कर दिये हैं.

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त मारोश शेफचोविच के साथ लंबी और गहन व्यापार वार्ता की. इन चर्चाओं में यूरोप के विवादास्पद कार्बन कर और कृषि सब्सिडी पर भारत की आपत्ति जैसे कुछ संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं.

एफटीए वार्ता गणतंत्र दिवस से पहले पहुंचे निष्कर्ष पर

भारत और यूरोपीय संघ का प्रयास है कि एफटीए वार्ता गणतंत्र दिवस से पहले सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंच जाए. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा इस वर्ष गणतंत्र दिवास पर सरकार के अतिथि होंगे. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र के पूर्व प्रमुख प्रो. बिस्वजीत धर ने कहा, जहां तक मेरी जानकारी है, हम बहुत करीब हैं-काफी करीब. यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टैक्स और श्रमिकों की आवाजाही से जुड़ी भारत की मांगों पर समझौते के रास्ते निकल रहे हैं.

वैश्विक कारकों से तय होगी बाजार की दिशा

मुंबई, 11 जनवरी. घरेलू शेयर बाजारों में बीते सप्ताह 2.5 प्रतिशत की बड़ी गिरावट के बाद आने वाले सप्ताह में निवेशकों की नजर घरेलू स्तर पर कंपनियों के तिमाही परिणामों और वैश्विक कारकों पर होगी. चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के आंकड़े आने शुरू हो गये हैं.

आज 12 जनवरी को प्रौद्योगिकी कंपनियों एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टाटा समूह की टीसीएस के वित्तीय नतीजे जारी किये जाने हैं. इसके बाद 15 जनवरी को इसी क्षेत्र की इंफोसिस और 16 जनवरी को टेक महिंद्रा के नतीजे आयेंगे. 17 जनवरी को एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आयेंगे. कुछ और प्रमुख बैंकों के परिणाम भी सप्ताह के दौरान जारी किये जाने हैं. इसके अलावा निवेशक वैश्विक स्तर पर जारी व्यापार और भू-राजनीतिक उथल-पुथल पर भी नजर बनाये हुए हैं. इस सभी कारकों का असर बाजार पर देखा जायेगा. बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 2,185.77 अंक (2.55 प्रतिशत) टूटकर सप्ताहांत पर 83,576.24 अंक पर बंद हुआ.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 645.25 अंक यानी 2.45 प्रतिशत की साप्ताहिक गिरावट में 25,683.30 अंक पर आ गया. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक में 2.34 फीसदी और स्मॉलकैप-100 सूचकांक में 3.08 फीसदी की साप्ताहिक गिरावट रही. बीते सप्ताह सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 19 के शेयर लाल निशान में और अन्य 11 के हरे निशान में रहे. ट्रेंट का शेयर सबसे अधिक 9.82 प्रतिशत टूट गया. रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर भी 7.36 प्रतिशत लुढ़क गया.

सप्ताह के दौरान महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 3.28 प्रतिशत, एलएंडटी का 3.27, कोटक महिंद्रा बैंक का 3.11, बजाज फाइनेंस का 3.04, मारुति सुजुकी का 2.71, टाटा स्टील का 2.49 और बजाज फिनसर्व का 2.23 फीसदी गिर गया. टेक महिंद्रा का शेयर 1.94 फीसदी, इंफोसिस का 1.58 और टीसीएस का 1.30 प्रतिशत नीचे बंद हुआ. बीईएल में सबसे अधिक 3.91 प्रतिशत की साप्ताहिक तेजी रही.

वेकोलि की कार्य संस्कृति सर्वोत्कृष्ट : साईराम

कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष वेकोलि के दौरे पर रहे

नागपुर, 11 जनवरी। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक बी. साईराम दिनांक 10 एवं 11 जनवरी, 2026 को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) के दो दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों एवं परियोजनाओं का निरीक्षण किया।

अपने दौरे के द्वितीय दिवस दिनांक 11 जनवरी, 2026 को साईराम ने वेकोलि मुख्यालय में उत्पादन, गुणवत्ता, प्रेषण, पर्यावरण संरक्षण, सीएसआर तथा भविष्य की योजनाओं से संबंधित विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में साईराम ने टीम वेकोलि की कार्य संस्कृति तथा कार्य निष्पादन की सराहना करते हुए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में बेहतर परिणाम की अपेक्षा जताई। उन्होंने उपभोक्ता संतुष्टि, कोयले की गुणवत्ता, नई तकनीक के व्यापक इस्तेमाल, खनन कार्य में सुरक्षा एवं समुचित नियोजन पर जोर दिया।

उन्होंने कोयले की यातायात की स्थिति पर विस्तार से जानकारी हासिल की तथा इस दिशा में वृद्धि हेतु अपने सुझाव दिए। उन्होंने कोयला उद्योग के बदलते परिपेक्ष में वेकोलि की भूमिका पर विस्तार से बात की। समीक्षा बैठक में वेकोलि के सीएमडी जे. पी. द्विवेदी ने वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों तथा योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया की वेकोलि इस वित्तीय वर्ष में भी कोयला उत्पादन का टारगेट हासिल करेगा।

सीतारमण ने राज्यों से बजट सुझाव लिए

2026-27 बजट- राज्यों के साथ चर्चा शुरू

वित्त मंत्री ने राजधानी में विचार-विमर्श किया

नई दिल्ली, 11 जनवरी. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट की तैयारियों के सिलसिले में राज्यों और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के साथ शनिवार को यहां एक उच्चस्तरीय बैठक की और उनकी वित्तीय प्राथमिकताओं, विकास संबंधी आवश्यकताओं को सुना.

वित्त मंत्री ने उनसे 2026-27 के बजट को लेकर उनके सुझाव प्राप्त किये. बैठक में मणिपुर के राज्यपाल, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और सिक्किम के मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री तथा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल थे.

इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी, मंत्रालय के आर्थिक कार्य, व्यय और राजस्व विभागों के सचिव और कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्रीमती सीतारमण ने देश के विकास में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि केंद्र जमीनी स्तर की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले बजट के निर्माण में राज्य सरकारों के रचनात्मक और व्यावहारिक सुझावों को महत्व देता है. सूत्रों के अनुसार कई राज्यों ने पूंजीगत व्यय के लिए बढ़े हुए समर्थन, उधारी सीमा में लचीलापन, और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए अधिक आवंटन जैसे मुद्दे उठाए.

राष्ट्रीय सहकारिता कार्यशाला में सुधार पर बल

पैक्स और बहु-राज्यीय समितियों के सुधार पर चर्चा

उदयपुर (राजस्थान), 11 जनवरी. सहकारिता क्षेत्र पर यहां दो दिवसीय राष्ट्रीय-स्तरीय कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस को सुदृढ़ करने और बहु-राज्य सहकारी समितियों में सुधारों को आगे बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया.

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार सहकार से समृद्धि के मोदी सरकार के आह्वान की भावना के अनुरूप सहकारी संस्थाओं को समावेशी विकास, ग्रामीण समृद्धि तथा जमीनी स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम बनाने के केन्द्र सरकार के वृहद उद्येश्यों के साथ यह आयोजन शुक्रवार को सम्पन्न हुआ. कार्यशाला का एक अन्य प्रमुख फोकस राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस को सुदृढ़ करने और बहु-राज्य सहकारी समितियों में सुधारों को आगे बढ़ाने पर रहा.

एसबीआई ऑटो एक्सपो 2026 का भव्य आगाज

नई दिल्ली, 11 जनवरी. देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर की रफ्तार को और तेज करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जमशेदपुर में ऑटो एक्सपो 2026 का भव्य शुभारंभ किया है. इस दो दिवसीय एक्सपो में देश के प्रमुख वाहन निर्माता एक साथ अपने नए और प्रीमियम मॉडल लेकर पहुंचे हैं. आम ग्राहकों से लेकर व्यवसायिक खरीदारों तक, सभी के लिए यह एक्सपो एक ही स्थान पर मल्टी-ब्रांड विकल्पों की सुविधा दे रहा है. खास बात यह है कि यहां सिर्फ गाड़ियां देखने का ही नहीं, बल्कि तुरंत फाइनेंस की सुविधा भी दी जा रही है.

शीर्ष 10 कंपनियों के एमकैप में गिरावट

रिलायंस, एचडीएफसी बैंक ने झेला बड़ा नुकसान

मुंबई, 11 जनवरी. घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह रही बड़ी गिरावट के बीच बीएसई की शीर्ष 10 में शामिल सात कंपनियों का सम्मिलित बाजार पूंजीकरण (एमकैप) 3,63,412 करोड़ रुपये घट गया जबकि अन्य तीन का एमकैप 41,599 करोड़ रुपये बढ़ा.

बाजार पूंजीकरण के मामले में लंबे समय से शीर्ष पर रहने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज को सप्ताह के दौरान 1,58,533 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और सप्ताहांत पर उसका एमकैप घटकर 19,96,446 करोड़ रुपये रह गया. सप्ताह के दौरान उसका शेयर 7.36 प्रतिशत गिरा था. निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक का एमकैप 96,154 करोड़ रुपये गिरकर 14,44,150 करोड़ रुपये रहा. वह अब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरे नंबर पर बरकरार है. बाजार पूंजीकरण के मामले में भारती एयरटेल बीते सप्ताह 45,275 करोड़ रुपये के नुकसान के साथ तीसरे स्थान से फिसलकर चौथे स्थान पर आ गयी. अब 11,60,682 करोड़ रुपये के साथ टीसीएस ने शीर्ष तीन में जगह बना ली है.

समाचार विशेष

कई दिग्गजों की आरजेडी से होगी छुट्टी?

तेजस्वी यादव चलाएंगे सफाई अभियान, बिहार में मच गया सियासी हड़कंप

पटना. करीब एक महीने तक राजनीतिक सुर्खियों से दूर रहने के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश यात्रा से लौट आए हैं. फिलहाल वे दिल्ली में हैं लेकिन जल्द ही उनके पटना पहुंचने की संभावना है. उनके वापस आते ही सूबे की सियासत में हलचल तेज हो गई है.

क्योंकि बड़ा एक्शन होने वाला है. बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव पार्टी के भीतर एक बड़ा 'सफाई अभियान' चलाने की तैयारी में हैं, जिसका असर संगठन से लेकर बड़े नेताओं तक पर दिख सकता है और कई कड़े फैसले लिए जा सकते हैं. क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद से ही आरजेडी मुश्किल दौर से गुजर रही है.

चुनाव में 25 सीटों पर सिमटी पार्टी- विधानसभा चुनाव में पार्टी केवल 25 सीटों पर सिमट गई और लालू परिवार में भी कलह खुलकर सामने आ गई. बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों संजय यादव व रमीज खान पर बदसलूकी के आरोप लगाकर नाता तोड़ लिया, जबकि बड़े भाई तेज प्रताप यादव पहले ही परिवार से अलग हैं. अब तेजस्वी के लौटने के बाद संगठन में बड़े बदलाव और कड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है.

प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर खतरा

पार्टी में निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर नए चेहरों को मौका देने की भी पूरी योजना तैयार है, खासकर आगामी पंचायत चुनावों को देखते हुए तेजस्वी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल की कुर्सी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं. पिछले साल जून में ही उन्होंने जगदानंद सिंह की जगह ली थी, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी को बुरी हार मिली. अब चर्चा है कि बिहार में आरजेडी की कमान किसी मजबूत चेहरे को सौंपी जा सकती है, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है.

नतेशन विवाद में फंसे विजयन

तिरुवनंतपुरम. केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. किसी न किसी मुद्दे को लेकर गठबंधन की दोनों बड़ी पार्टियों सीपीएम और सीपीआई के बीच विवाद चल रहा है. सीपीआई के राज्य सचिव और सांसद विनय विस्वम इस मामले में सबसे ज्यादा मुखर हैं.

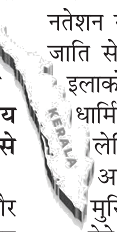

वे लगातार सीपीएम और उसके मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन को निशाना बना रहे हैं. पिछले दिनों उन्होंने इस बात के लिए राज्य सरकार पर हमला किया था उसने केंद्र सरकार के फंड के लिए बुनियादी सिद्धांतों से समझौता किया और नई शिक्षा नीति को स्वीकार करने की पहल की. अब नया विवाद वेलापल्ली नतेशन का है. नतेशन के विचारों और भाषणों से राज्य के अल्पसंख्यकों में नाराजगी है. गौरतलब है कि नतेशन राज्य की पिछड़ी ऐझवा जाति से आते हैं, जिसका कई इलाकों में बड़ा असर है. वे एक धार्मिक संगठन के प्रमुख भी हैं. लेकिन वे लगातार राज्य के अल्पसंख्यकों खास कर मुस्लिमों के खिलाफ बयान देते रहते हैं. वे खासतौर से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के खिलाफ मुखर रहते हैं. हालांकि मुस्लिम लीग का गठबंधन कांग्रेस के साथ है लेकिन उस पर हमला करते हुए नतेशन मुसलमानों पर भी आक्रामक हो जाते हैं.

भूपेश बघेल जाएंगे राज्यसभा!

बेटे चैतन्य की राजनीति में एंट्री की भी चर्चा

रायपुर. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के राज्यसभा जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस हाईकमान उन्हें राज्यसभा भेजने पर विचार कर रहा है, जहां छत्तीसगढ़ से दो सीटें खाली हो रही हैं. इस चर्चा को बल इसलिए भी मिल रहा है कि क्योंकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भूपेश बघेल को अग्रिम बधाई तक दे डाली है.

इस बीच, बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के राजनीति में उतरने की चर्चाएं भी जोरों पर हैं. चैतन्य हाल ही में कथित शराब घोटाले में ईडी और ईओडब्ल्यू के मामलों में जमानत पर रिहा हुए हैं. बघेल ने इसे राजनीतिक साजिश बताया था और कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत कहा. इस मामले में भूपेश बघेल ने कहा था, पहले उनके बेटे चैतन्य को कोई नहीं जानता था. अब उन्हें सब जानने लगे हैं. भूपेश बघेल के इस बयान के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि भूपेश बघेल राज्यसभा जा सकते हैं और उनके बेटे चैतन्य बघेल राजनीति में उतर सकते हैं.

राज्यसभा में दो सीटें होंगी खाली- राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की 5 सीट हैं. इनमें से 2 सीट 9 अप्रैल 2026 को खाली होने वाली हैं.

बता दें कि सांसद फूलो देवी नेताम और केटीएस तुलसी का कार्यकाल समाप्त होने वाला है. बघेल पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भी हैं और हाल ही में बिहार चुनाव में वरिष्ठ पर्यवेक्षक की भूमिका निभा चुके हैं. इससे पहले, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की दो सीटें बाहरी लोगों को दी गई थीं. अब स्थानीय नेता को मौका देने की मांग भी उठ रही है.

हर व्यक्ति को राजनीति में आने का अधिकार

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बघेल को राज्यसभा जाने की अग्रिम बधाई तक दे दी है. उन्होंने कहा, दोनों सीटें पहले बाहरी लोगों को दी गई थीं, राज्यसभा जाने से कोई दिक्कत नहीं. हर व्यक्ति को राजनीति में आने का अधिकार है. बेटे चैतन्य बघेल के राजनीति में आने पर हमें कोई आपत्ति नहीं. जायसवाल ने पहले भी बघेल सरकार पर शराब घोटाले के आरोप लगाए थे. यह बयान ऐसे समय में आया है, जब 2026 में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं.

विशेष — कांग्रेस और भाजपा ने इसे गलत बताते हुए अपने स्थानीय नेताओं पर की कार्रवाई

बिखर गया भाजपा-कांग्रेस-एआईएमआईएम गठबंधन

मुंबई. महाराष्ट्र की सियासत में आज कुछ ऐसा हुआ, जिसने राज्य की सीमाओं को तोड़कर देश में सुर्खियां बटोरी. नगरपालिका नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस और एआईएमआईएम से बीजेपी के गठबंधन ने सियासी भूचाल ला दिया.

हालांकि, स्थानीय स्तर पर नेताओं की जुगत से हुए ये गठबंधन बहुत देर तक टिके नहीं क्योंकि अपनों ने ही सवाल उठाने शुरू कर दिए. इसके बाद दोनों (बीजेपी-कांग्रेस) ओर से पार्टी आलाकमान ने एक्शन लिया और गठबंधन टूट गए. कांग्रेस ने अंबरनाथ जिला अध्यक्ष के खिलाफ एक्शन लिया है. वहीं, अकोला जिले के आकोट नगर परिषद में बीजेपी ने अपने विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आइए इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं और ये भी जानते हैं कि किस नेता ने क्या कहा.

सबसे पहले बात अकोला जिले के अकोट की. यहां एआईएमआईएम से गठबंधन के पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने विधायक प्रकाश भारसखले को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उन पर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप है. नोटिस में विधायक से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि एआईएमआईएम के साथ तथाकथित गठबंधन के बाद पार्टी की छवि क्यों और कैसे प्रभावित हुई. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इस घटनाक्रम से संगठन की साख को नुकसान पहुंचा है. बीजेपी सूत्रों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आगे और कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं. इस घटनाक्रम से राज्य की सियासत में नई बहस छिड़ गई है. जबकि पार्टी स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. ये बिना अनुमति लिया गया गलत फैसला था.

बीजेपी से गठबंधन पर आलोचना झेलने के बाद कांग्रेस ने साफ किया कि यह गठबंधन पार्टी नेतृत्व की अनुमति के बिना किया गया था. कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे और प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है और स्थानीय स्तर पर बिना अनुमति लिया गया गलत फैसला था, जिस पर कार्रवाई की जा रही है.

इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है और ऐसे मामलों में उचित निर्णय लिया जाएगा. अंबरनाथ नगर परिषद में बना यह अल्पकालिक गठबंधन अब महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है. कुछ ही घंटों में टूटे इस राजनीतिक प्रयोग ने दोनों दलों को असहज स्थिति में लाकर खड़ा किया है.